

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 29/22

GCMS NO 2022/51



1. सुखराम पुत्र भजनी (मृतक)

1/1. रामराज

/2. पुखराज

/3. मुनेश पुत्रान स्व०सुखराम

/4. सुगमा देवी बेवा स्व०सुखराम

शिवलाल पुत्र भजनी (मृतक)

2/1. ऋषिकेश

2/2. अनिल पुत्रान स्व०शिवलाल

2/3. बादामी देवी बेवा स्व०शिवलाल

2/4. सीमा

2/5. नरसो पुत्रियान स्व० शिवलाल

3. रामपति पत्नि भजनी (मृतक हजफ) जातियान मीना निवासीयान कोयला तहसील वामनवास अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वामनवास

2. महेश पुत्र भजनी जाति मीना कोयला तहसील वामनवास

रेस्पों

(अपील विरुद्ध मु०नं० 11/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.20 न्यायालय उप जिला कलेक्टर वामनवास)

अभिभाषक अपीला० श्री योगेश शर्मा

अभिभाषक रैस्पों पैरोकार सरकार एवं श्री श्याम मोहन शर्मा

दिनांक 03.09.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.20 न्यायालय उप जिला कलेक्टर वामनवास की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट व रेस्पों संख्या 2 द्वारा वाद पत्र घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख०न० 50 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा स्थित ग्राम कोयला तहसील वामनवास है। जो वादीगण 1 ता 3 के पिता व वादिया संख्या 4 के पति भजनी पुत्र भोरया की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी रही है। भजनी का देहान्त हो चुका है वादीगण ही उसके वारिसान है। उक्त आराजीयात को वादीगण भजनी के जिवित अवस्था से व फौत होने के बाद लगातार वहैसियत खातेदार काबिज रहकर काशत करते चले आ रहे है। हाल भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक ख०न० 50



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

के नये ख0न0 123 रकबा 3 ऐयर, 125 रकबा 22 ऐयर व खसरा न0 124 मे कुछ रकबा शामिल कर दिया जिसका खसरा न0 123 की खातेदारी तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के नाम दर्ज अर्थात् लेकिन खसरा न0 124 व 125 को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी साबिक अनुसार वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों को वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को बिना किसी अधिकार के दर्ज करने का अधिकार नहीं था यहाँ तक कि साबिक रिकार्ड मे भी ख0न0 124 जैसा स्थान नहीं था। भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा मनमाने तौर पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण की खातेदारी की भूमि को गलत प्रकार से सिवायचक व गैर मुमकिन रास्ता खसरा न0 124 मे शामिल कर दिया जबकि साबिक रिकार्ड के अनुसार ही पुनरावृत्ति करनी चाहिए थी। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी की भूमि को गलत प्रकार से हटाकर सिवायचक दर्ज कर अपने अधिकारो का दुरुपयोग किया है। प्रतिवादी द्वारा यदि वादीगण को उनके कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को भारी आघात होगा। इसलिए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का नोटिस दिये जाने के कारण वादी कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वादीगण साबिक ख0न0 50 से बने हाल खसरा न0 ख0न0 124 का 5 ऐयर (खसरा न0 123 व 125 के मध्य का भाग) व ख0न0 125 का सम्पूर्ण 22 ऐयर स्थित ग्राम कोयला तहसील बामनवास का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती फरमाई जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण /अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंड को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे प्रकरण मे विरचित तनकीयात का भी विवेचन नहीं किया है ना ही वादी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया है। इस प्रकार तनकीयात का विवेचन ना कर तथा साक्ष्य का अवलोकन ना कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन ना कर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे वादी के वादपत्र को दस्तावेजो के आधार पर साबित मानते हुए भी गलत निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही प्रतिवादीगण को कानून से उपर उठकर अनुतोष देने का मन बना लिया हो जो कि गलत है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का


रजिस्टर अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र मे वादी संख्या 1 बाहर रहता है इसलिए उसे प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.3.20 व डिक्री दिनांक 28.3.20 निरस्त किया जाकर वादीगण का डिक्री फरमाया जावे।



रेसपो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपीलांट के कथन का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

रेसपो0 संख्या 1 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस मे बताया कि भूमि हाल खसरा न0 123 रकबा 0.03 व 125 रकबा 0.22 ऐयर साबिक ख0न0 50 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा से बने है। जो जमाबंदी सम्वत 2028 से 2031 से स्पष्ट है। जबकि हाल खसरा न0 124 रकबा 0.26 है0 साबिक ख0न0 33 मिन , 36 मिन, 32 मिन व 50 मिन से बना है। हाल खसरा न0 124 के सम्पूर्ण भाग पर वादीगण का कब्जा काशत नही रहा है। भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके के अनुसार ही सिवायचक दर्ज किया है। इसी प्रकार वादीगण खसरा न0 125 रकबा 0.22 है0 मे से रकबा 0.14 है0 पर ही काबिज है। साबिक रिकार्ड मे भूमि साबिक खसरा न0 50 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा भूमि की किस्म तालाबी दर्ज है। जो प्रदर्श 4 से स्पष्ट है। इस प्रकार तालाबी भूमि पर वादीगण के अधिकार सृजित नही हो सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तालाबी भूमि पर वादीगण के अधिकार नही होने से दावा विधिक रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि हाल भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक ख0न0 50 के नये ख0न0 123 रकबा 3 ऐयर, 125 रकबा 22 ऐयर व खसरा न0 124 मे कुछ रकबा शामिल कर दिया जिसका खसरा न0 123 की खातेदारी तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के नाम दर्ज कर दी लेकिन खसरा न0 124 व 125 को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी रिकार्ड अनुसार वादीगण की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी रही है। भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों को वादीगण की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी को बिना किसी अधिकार के सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नही था। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अधार वर्ष 2028 से 2031 मे आरजी साबिक ख0न0 50 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा भजनी पुत्र भौरया के नाम दर्ज है परन्तु भूमि की किस्म तालाबी दर्ज है। जबकि अपीलांट का कथन रहा कि भूमि काशत की आराजी है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये एवं बिना तनकीयात को विचरीत कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट के इस कथन की पुष्टि अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का भी विवेचन नही किया है। जबकि घोषणा के वाद मे वादी एवं प्रतिवादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही सही तथ्य



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय के समक्ष आते हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के तहत पारित नहीं कर केवल मात्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को आधार बनाकर ही पारित किया गया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को वादी एवं प्रतिवादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है।

अतः अपील अपीलांत रिमाण्ड योग्य होने रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 11/12 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.20 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.9.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(लेदमी कांत बालोत)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर